

- अंडमान निकोबार में बढ़ते हवाई किराए पर सांसद बिष्णु पद रे चिन्ता जताते हुए केन्द्र सरकार से ठोस कदम उठान की मांग की।
- अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कक्षा पहली से आठवीं तक निजी स्कूलों में पच्चीस प्रतिशत सीटें निर्धन और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित की गई।
- अंडमान निकोबार पुलिस ने डिजीटल जांच में हुए खुलासे के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी मामले में प्रमुख सह आरोपी को गिरफ्तार किया।
- समुद्री संसाधनों की सुरक्षा के लिए मत्स्य विभाग ने उठाया बड़ा कदम। द्वीप समूह में इक्कसठ दिनों तक मछली पकड़ने पर अस्थायी प्रतिबंध रहेगा।



सांसद बिष्णु पद रे ने अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और मुख्यभूमि के बीच बढ़ते हवाई किराए को लेकर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किन्जरापु को पत्र लिखकर किराए को नियंत्रित करने की अपील की। सांसद ने बताया कि श्री विजयपुरम से चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम के लिए एकतरफा हवाई किराया 18,000 रूपए से 35,000 रूपए तक पहुंच रहा है, जबकि पीक सीजन में यह 50,000 रूपए तक हो जाता है, जो अन्य समान दूरी के रूट्स से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि द्वीपों में रहने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा ही मुख्य साधन है, और महंगे किराए के कारण मरीजों, छात्रों और कामकाजी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सांसद ने सरकार से किराए पर सीमा तय करने, उड़ानों की संख्या बढ़ाने, UDAN योजना को मजबूत करने और मनमानी बढ़ोतरी पर निगरानी रखने की मांग की है।



अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी निजी विद्यालयों को कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रावधान बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के तहत लागू किया गया है। निजी स्कूलों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्रत्येक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आसपास के क्षेत्र के कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रखनी होंगी। इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही, जिन स्कूलों में प्री-स्कूल (पूर्व-प्राथमिक) शिक्षा दी जाती है, वहां भी यही नियम लागू रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र अभिभावकों को अपने-अपने क्षेत्र के ज़ोनल अधिकारियों से संपर्क कर प्रवेश फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म 6 अप्रैल से उपलब्ध होंगे। अभिभावकों को निर्देश दिया गया है कि वे भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 10 अप्रैल तक संबंधित ज़ोनल अधिकारी के पास जमा करें। प्रशासन ने सभी निजी विद्यालयों को इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके।



देश भर में जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना कर परिवारों के पास उपलब्ध संपत्तियों और सुविधाओं से संबंधित डेटा और द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मकान सूचीकरण 16 अप्रैल से 15 मई और जनसंख्या गणना फरवरी, 2027 में आयोजित की जाएगी। 'डिजिटल इंडिया' के तहत, डेटा संग्रह की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। आम जनता के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल [se.census.gov.in](http://se.census.gov.in) के माध्यम से स्व-गणना का प्रावधान किया गया है। यह पोर्टल 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। स्व-गणना प्रक्रिया एक सुरक्षित और लचीला तरीका है, जिससे परिवार अपनी सुविधा अनुसार विवरण दे सकते हैं। परिवार का कोई भी एक सदस्य लगभग 15-20 मिनट में विवरण भर सकता है। विवरण भरने के बाद मोबाइल या ईमेल पर एक स्व-गणना आईडी प्राप्त होगी, जिसे प्रगणक के साथ साझा करना होगा। जनगणना संचालन निदेशालय, ने सभी से स्व-गणना के माध्यम से डेटा प्रदान करने की अपील की है।



दक्षिण अंडमान में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य समिति ने दक्षिण अंडमान उपायुक्त पूर्वा गर्ग के मार्गदर्शन में श्रम आयुक्त कार्यालय, श्री विजय पुरम में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शहरी कमजोर वर्ग के लिए बीपी, शुगर, वजन जांच, टीबी स्क्रीनिंग और चेस्ट एक्स-रे जैसी सुविधाएं प्रदान की गईं। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए भी विशेष शिविर लगाए गए,

जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि टीबी के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। यह पहल टीबी मुक्त भारत मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।



अंडमान एवं निकोबार पुलिस ने नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रमुख सह-आरोपी ए. नागनाथन को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कावूर हेमंत राव को एक दशमलव पांच छ शून्य किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था। जांच में वित्तीय लेन-देन और डिजिटल रिकॉर्ड की समीक्षा के दौरान ए. नागनाथन का नाम सामने आया, जिन्होंने नशीले पदार्थों की आपूर्ति में मदद की। गिरफ्तारी से ड्रग नेटवर्क के वित्तीय और संचालन लिंक उजागर हुए हैं। इस मामले की जांच एएसआई सूर्य नारायण के नेतृत्व में और निरीक्षक के. बिनोज की निगरानी में हुई, जबकि समग्र निगरानी उप-अधीक्षक स्मृति योगिता शर्मा और डीआईजी जितेंद्र कुमार मीना ने की।



समुद्री संसाधनों के संरक्षण और समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग ने मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध लागू किया गया है। जारी सूचना के अनुसार, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में प्रादेशिक जल सीमा से बाहर सभी मछली पकड़ने वाले जहाजों पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी यह प्रतिबंध 15 अप्रैल से 14 जून तक कुल 61 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। वहीं पश्चिमी तट पर यह प्रतिबंध 1 जून से 31 जुलाई तक लागू रहेगा। पारंपरिक गैर-मशीनीकृत नौकाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। विभाग ने सभी मछुआरों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि का सख्ती से पालन करें, ताकि मत्स्य संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और समुद्र में सुरक्षा बनी रहे।



वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुफ्त वाई-फाई और उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री, किंजरापु राममोहन नायडू ने हाल ही में देश के 57 हवाई अड्डों पर मुफ्त वाई-फाई सेवाओं सहित उन्नत यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। यात्री सुविधाओं के उन्नयन के राष्ट्रव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में, कई हवाई अड्डों पर एक साथ मुफ्त वाई-फाई सेवा के साथ-साथ उड़ान यात्री कैफे, डिजी यात्रा सुविधा, अवसर आउटलेट, फ्लाईब्रेरी और किड ज़ोन जैसी कई अन्य सुविधाएं शुरू की गईं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों और प्रमुख हितधारकों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से उद्घाटन समारोह में भाग लिया। वाई-फाई सेवा को यात्रियों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय के नेतृत्व में किए गए इन सुधारों का उद्देश्य हवाई अड्डों पर आधुनिक यात्री सेवाएँ प्रदान करना है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष जोर दिया गया है।



भारतीय सेना में होने वाली भर्ती की तिथि को बढ़ाकर अब 10 अप्रैल कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) पर पंजीकरण कर सकते हैं। निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों से पंजीकरण करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों को सही ढंग से अपलोड करने को कहा गया है।



चाथम स्थित सरकारी आरा मिल में वार्षिक भौतिक सत्यापन और वार्षिक रखरखाव का कार्य किया जाएगा। इसे देखते हुए चीरी हुई लकड़ी की बिक्री आज से 15 अप्रैल तक बंद रहेगी।

